अमृत मिशन – मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम

- भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें जैसे की स्वच्छ भारत मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया एवं अमृत आदि देश भर में क्रियान्वयित की जा रहीं हैं। मध्य प्रदेश राज्य भारत सरकार की इन योजनाओं को अमल में लाने में सदैव अग्रणी रहा है।
- अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एण्ड अर्बन टांसफोर्मेशन (AMRUT) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो भारत वर्श के विभिन्न नगरीय निकायों में बेसिक इंफास्टक्चर डेवलपमेन्ट एवं हरित विकास हेतु समर्पित है।
- मध्यप्रदेश में यह योजना वर्श 25 जून 2015 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत जल प्रदाय, सीवरेज, स्टार्म वाटर डनेज, हरित क्षेत्र विकास एवं अर्बन टांसपोर्ट घटकों को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 33 शहरों में एवं धर्मिक महत्व के एक शहर ओंकारेश्वर सहित कुल 34 शहरों में विकसित किया जाना है।
- मध्यप्रदेश में अमृत योजना के अंतर्गत राशि रू. 6459.78 करोड़ की राज्य वार्शिक कार्य योजना (SAAP) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। जल प्रदाय हेतु रू. 2202.70 करोड़, सीवरेज हेतु रू. 3581.20 करोड़, स्टार्म वाटर डनेज हेतु रू. 263.01 करोड़, अर्बन टांसपोर्ट हेतु रू. 261.89 करोड़ एवं हरित क्षेत्र विकास हेतु रू. 150.98 करोड़ आवंटित किये गये हैं। इस मिशन के तहत 199 योजनाओं का समावेश किया गया है, जिनमें से 15 शहरों की 42 परियोजनाए जिनकी कुल लागत रू. 256.56 करोड़ है का कार्य पर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 33 शहरों में 157 परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत हैं जिनकी कुल लागत रू. 6448.85 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। इस योजना में अब तक रू. 2572.90 करोड़ का व्यय हो चुका है।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात 714224 घरों में एवं अन्य योजनाओं के कन्वर्जेन्स से 476149 घरों में जल प्रदाय तथा 1019205 घरों में एवं अन्य योजनाओं के कन्वर्जेन्स से 179859 घरों में सीवेज के कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। मध्यप्रदेश के 34 शहरों में 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 11631399 जनसंख्या अमृत योजना से लाभान्वित होगी। अमृत मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना का उन्नयन है।

- प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पीडीएमसी के रूप में प्रदेश के पूर्वी भाग के 17 शहरों हेतु ईजिस इंडिया लिमिटेड एवं पश्चिमी भाग के 17 शहरों हेतु वाप्कोस लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा नियुक्त Independent Review & Monitoring Agency (IRMA) के रूप में शाह टेक्निकल कन्सल्टेन्ट द्वारा स्वतंत्र निगरानी का कार्य किया जा रहा है।
- राज्य द्वारा विगत 3 वर्षों से लगातार शहरी सुधार कार्यक्रम पूर्ण कर रिफार्म इंसेन्टिव के रूप में क्रमशः राशि रू. 33.45 करोड़, रू. 63.75 करोड़ एवं रू. 34.00 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त की गई है। इस मद में प्रदेश सरकार द्वारा भी समानुपातिक राशि प्रदान की जा रही है।
- प्रदेश के 34 नगरीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग कराई गई है। प्राप्त रेटिंग के आधार पर प्रदेश के इंदौर एवं भोपाल शहरों द्वारा परियोजनाओं के निकाय अंश की प्रतिपूर्ति हेतु म्युनिसिपल बांड जारी किये गये हैं। म्युनिसिपल बांड जारी करने पर इंदौर एवं भोपाल को क्रमशः राशि रू. 18.18 करोड़ एवं रू. 22.45 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन शहरों हेतु म्युनिसिपल बांड जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।
- एसटीपी एवं डब्ल्यूटीपी के पम्प्स एवं मोटर्स का एनर्जा ऑडिट भारत सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी ईईएसएल द्वारा किया जा रहा है। ईईएसएल द्वारा 28 शहरों की एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिनमें से 20 शहरों की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा किया जा चुका है, पम्प रिप्लेसमेन्ट का काय प्रक्रियाधीन है।
- अमृत शहरों में 507972 परम्परागत स्टोट लाइट में से 161868 स्टोट लाइट को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट से रिप्लेस किया जा चुका है।
- अमृत मिशन में परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रदेश निरन्तर देश के सर्वश्रेश्ठ 5 प्रदेशों में सम्मिलित है।

- उल्लेखनीय है कि प्रदे" ा की सीहोर सीवरेज परियोजना के 12 MLD STP को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 23 जून 2018 को लोकार्पित किया गया यह योजना अमृत योजना अंतर्गत सीवेज परियोजना में सर्वप्रथम है। SBR Technology पर आधारित इस योजना से मलजल को संशोधित कर 10 BOD जल प्राप्त किया जा रहा है। अन्य शहरों में भी सीवरेज का कार्य प्रगति पर है। सीवरेज परियोजना लागू होने से आस पास के इलाकों में गंदी बदबू, प्रदूषण आदि से राहत मिलती है।
- जल प्रदाय के क्षेत्र में भोपाल (भौंरी), इन्दौर, सीहोर, बैतूल एवं खंडवा आदि योजनाओं को पूर्ण कर पूरे शहर में PLC-SCADA के द्वारा मानीटरिंग कर स्वच्छ जल प्रदाय किया जा रहा है।
- भोपाल, मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर, रीवा, दमोह, सतना तथा देवास आदि शहरों में स्टॉर्म वाटर डेनेज का कार्य प्रगति पर है।
- हरित क्षत्र विकास में भी मध्य प्रदेश के 42 पार्कों में से 32 पार्कों पर कार्य पूर्ण हो चुका है एवं आस–पास के लोगों द्वारा इसका भरपूर लाभ उठाया जा रहा है।
- 18 शहरों में अर्बन ट्रांसपोर्ट का कार्य प्रगति पर है। अमृत मिशन अंतर्गत संचालित इंटर सिटी एवं इंट्रा सिटी में मिनी एवं मिडी बसों के चलन से जन –मानस में खुशी की लहर दौड गई है।
- अमृत योजना जन जीवन के स्तर के लगातार उन्नयन हेतु प्रगतिरत है।